taken the following measures to control degradation of the environment:—

(i) Department of Environment has been established to regulate the management of the environment and undertake surveillance for proper utilisation of the resources.

(ii) A Central Board has been set up for*the Prevention and Control of Water Pollution at the central level and in the States to regulate and management of water resources.

(iii) Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 has been enacted to regulate prevention of air pollution.

(iv) Insecticio.es Act has been enacted to regulate safe use of pesticides and insecticides to check its adverse effect on flora and founa.

(v) National Institute of Occupational Health, Ahmedabad, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, Central Insecticide Laboratory, Faridabad, Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow carry out research for identification and evaluation of health hazards due to environmental degradation at places of work and living.

(vi) Industries under organised sector are governed by Factories Act 1948 which regulates safety, health and welfare of workers employed in factories.

Supply of poor quality of rice and sugar at ration shops in Delhi

1575. SHRI M. BASAVARAJU: WiH the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES b$_e$ pleased to state:

(a) what is the fortnightly/monthly entitlement of rice for each adult member of a family, opting to draw rice from the ration shops as main item of consumption, in Delhi;

(b) what is the quantity of rice actually being supplied to the consumers in Circle No. 84, Lajpat Nagar New Delhi as compared to that in ' other circles;

(c) whether it is a fact that poor quality of sugar and rice are being supplied in circle No. 34 and consumers are compelled to purchase their requirements of rice and sugar from the open market- at $_v$ery high prices; and

(d) if so, what action Government have taken or propose to take to restore full quota of good quality rice and sugar to the consumers in the sai<5 circle?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M. S. SANJEEVI RAO); (a) At present one adult member of a family (from age of 12 years and above) holding rice-eater category of food card is entitled to get 16 kg rice per month from the fair price shop in Delhi.

(b) Rice as well as sugar are being supplied at the prescribed scale, subject to availability of stocks.

(c) No, Sir. According to standing instructions, food stuff of only prescribed specification is supplied to fair price shops by the Food Corporation of India.

(d) Does not arise, in view of (b) and (c) above.

Enforced sterlizations in Maharashtra

1576. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it has come to Government's notice that Government employees and- local leaders are coercing the Adivasis in Thane district of Maharashtra to go in for sterilization;

(b) whether it is a fact that a number of Adivasi males have become physically handicapped and are ne longer in a position to work as a resull thereof; and

(c) if so, what steps Government propose to take to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (MISS KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (c) As per information received from the State Government who are the implementing agency for the Family Planning Programme, detailed enquiries have been made into the allegations of coersion against Adivasis in Thane District for acceptance of sterilisation, and the same have not been found to be based on facts.

रेल मंत्रालय में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1577. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने यह निदेश दिया है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों और हिन्दी अधिसूचित कार्यालयों में सभी सरकारी काम-काज अनिवार्य रूप से हिन्दी में किये जायें, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य-क्रम को पूरी तरह क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और इस वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये भारत सरकार के नीति निदेशों के अनुसार बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि रेल मंत्रालय ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान रेलों पर हुई हिन्दी की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) हर वर्ष हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता आ रहा है जिसे सभी रेल कार्यालयों में कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दिया जाता है। वर्ष 1984-85 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। पूर्व रेलवे को छोड़कर, जहां हिन्दी में प्राप्त पत्रों के 99.4 प्रतिशत उत्तर हिन्दी में भेजे जाते हैं, अन्य क्षेत्रीय रेलों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के शत प्रतिशत उत्तर हिन्दी में भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार रेलवे बोर्ड द्वारा भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों में से 99 प्रतिशत पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

मूल पत्राचार के क्षेत्र में कार्यक्रम में यह निर्धारित है कि "क" क्षेत्र से जारी होने वाले कुल मूल पत्रों में से कम से कम 66.5 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र से 40 प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र से 10 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी होने चाहिएं। नौ क्षेत्रीय रेलों में से केवल उत्तर (फिरोजपुर मंडल को छोड़कर) तथा पूर्वोत्तर रेलें "क" क्षेत्र में स्थित हैं और इन रेलों से क्रमश: 87.1 प्रतिशत तथा 91.3 प्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं। पश्चिम और मध्य रेलें "क" और "ख" दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। पश्चिम रेलवे पर "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा क्रमश: लगभग 97.6 प्रतिशत तथा 50.7 प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। इसी प्रकार मध्य रेलवे द्वारा औसतन 88.3 प्रतिशत पत्र मूलरूप से हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा औ दक्षिण-पूर्व रेलों का अधिकांश भाग तथ